International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 8 Issue 10, October 2018,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता

डॉ0 केशरी नन्दन मिश्रा

एसोसिएट प्रोफेसर (इतिहास), हेमवती नन्दन बहुगुणा राजकीय पी.जी. कालेज, नैनी, इलाहाबाद

उत्तर प्रदेश, भारत।

सारांश

सहकारी एक संयुक्त स्वामित्व वाले और लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रित उद्यम के माध्यम से अपनी आम आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए स्वेच्छा से एकजुट व्यक्तियों का एक स्वायत्त संघ है। ILO सहकारी समितियों को विश्व स्तर पर महिलाओं और पुरुषों के रहने और काम करने की स्थिति में सुधार के साथ-साथ राज्य और निवेशक-संचालित उद्यमों द्वारा उपेक्षित क्षेत्रों में भी आवश्यक बुनियादी ढांचे और सेवाओं को उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण मानता है। सहकारिताओं के पास रोजगार सृजित करने और बनाए रखने का एक सिद्ध रिकॉर्ड है - उनका अनुमान है कि आज वे कम से कम 250 मिलियन रोजगार प्रदान कर सकते हैं; वे अच्छे काम को बढ़ावा देने और सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में योगदान करते हैं। इस पत्र का उद्देश्य सहकारी समितियों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को आगे बढ़ाना है क्योंकि महिलाएं आम तौर पर गरीबों में सबसे गरीब हैं और साथ ही, विकास प्रक्रिया में प्रमुख अभिनेताओं, महिलाओं के खिलाफ सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक भेदभाव को समाप्त करना एक है। गरीबी उन्मूलन, गुणवत्तापूर्ण परिवार नियोजन और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं को सुनिश्चित करने और जनसंख्या और उपलब्ध संसाधनों के बीच संतुलन हासिल करने की पूर्वापेक्षा। पत्र एक साहित्य समीक्षा है।

मुख्य शब्द: सहकारी, लोकतांत्रिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, गरीबी उन्मूलन, प्रजनन

प्रस्तावना

लैंगिक समानता से तात्पर्य जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरुषों और महिलाओं द्वारा समान अधिकारों, अवसरों और उपचार के आनंद से है। यह दावा करता है कि लोगों के अधिकार, जिम्मेदारियां, सामाजिक स्थिति और संसाधनों तक पहुंच इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि वे पुरुष या महिला पैदा हुए हैं या नहीं। लैंगिक समानता के सिद्धांत के लिए कई अंतरराष्ट्रीय समझौतों और संधियों में प्रतिबद्धताओं के बावजूद, दुनिया भर में महिलाओं को उत्पीड़न, भेदभाव और मानवाधिकारों के उल्लंघन का सामना करना पड़ रहा है। ये कई रूप लेते हैं, महिलाओं के खिलाफ हिंसा से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक महिलाओं की सीमित पहुंच तक। महिलाओं और पुरुषों के बीच

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 8 Issue 10, October 2018,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

असमानताएं भी काम की दुनिया में मौजूद हैं, नौकरी के अवसरों की मात्रा और रोजगार की गुणवत्ता दोनों में। औसतन, पुरुष समान कार्य करने वाली महिलाओं की तुलना में अधिक कमाते हैं, और पुरुष नेतृत्व और प्रबंधन पदों को भरना जारी रखते हैं। काम की दुनिया में लैंगिक समानता अवसर और उपचार की समानता, पारिश्रमिक की समानता और सुरक्षित और स्वस्थ कामकाजी वातावरण तक पहुंच, सहयोग और सामूहिक सौदेबाजी में समानता, सार्थक कैरियर विकास प्राप्त करने में समानता, मातृत्व सुरक्षा और काम और घर के बीच संतुलन का प्रतीक है। जीवन जो पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए उचित है। 2 यह संक्षिप्त प्रश्नों में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है जैसे: सहकारी उद्यम लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में कैसे मदद कर सकते हैं? ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे महिलाएं सहकारी लाभ का उपयोग उन अवसरों तक पहुँचने के लिए कर सकती हैं जो अन्यथा उन्हें नहीं दिए जाते हैं?

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहमत सहकारी मूल्य और सिद्धांत सहकारी आंदोलन को स्वयं सहायता, आत्म-जिम्मेदारी, लोकतंत्र, समानता, समानता और एकजुटता के मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध करते हैं। लोकतांत्रिक सदस्य नियंत्रण, एक सदस्य के एक वोट के आधार पर और लिंग के बिना, सामाजिक, नस्लीय, राजनीतिक या धार्मिक भेदभाव सहकारी मूल्यों के केंद्र में है।

सहकारी उद्यम महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण को प्राप्त करने में योगदान देने में भूमिका निभा सकते हैं। दुनिया भर से महिलाओं द्वारा अपने, अपने परिवार और अपने समुदायों का समर्थन करने के लिए सहकारी व्यवसाय मॉडल का उपयोग करने के प्रेरक उदाहरण हैं। हालाँकि, और भी बहुत कुछ है जो अंतर्राष्ट्रीय सहकारी आंदोलन महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को अपनी गतिविधियों और बदलाव के एजेंडे के केंद्र में रखने के लिए कर सकता है और करना चाहिए।

महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए चलाई जाने वाली सहकारी समितियां उन्हें अपनी आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए विशेष अवसर प्रदान कर सकती हैं, विशेष रूप से उन स्थितियों में जहां महिलाओं को सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है जो काम की दुनिया में भाग लेने की उनकी क्षमता को सीमित करते हैं। सहकारी समितियां जो अपने सदस्यों, उपयोगकर्ताओं और श्रमिकों के बीच घर और काम पर श्रम के लिंग विभाजन को ध्यान में रखती हैं और संबोधित करती हैं, उन समुदायों के लिए अधिक प्रासंगिक होने की संभावना है जिसमें वे काम करते हैं। केवल महिला सहकारी समितियां सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाओं को दूर करने में मदद कर सकती हैं जो अन्यथा कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को सीमित कर सकती हैं और विशेष रूप से लिंग-पृथक संदर्भों में प्रासंगिक हो सकती हैं।

सहकारिता में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण से संबंधित चुनौतियाँ

प्रत्येक प्रकाशन ने लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के संबंध में महिलाओं और सहकारी समितियों के लिए कुछ चुनौतियाँ प्रस्तुत कीं। हर प्रकाशन ने सभी चुनौतियों के बारे में बात नहीं की। निम्नलिखित चुनौतियाँ

सबसे अधिक उभरी हैं। आर्थिक अधिकारों और वित्त तक पहुंच के क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण की चुनौतियों को प्रतिबिंबित करने के लिए निष्कर्षों को समूहबद्ध किया गया है; सामाजिक, सांस्कृतिक और कानूनी अधिकार; और संगठनात्मक भागीदारी। महिलाओं की चुनौतियाँ सभी क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जिनमें स्वयं सहकारी, परिवार, समुदाय और व्यापक क्षेत्र शामिल हैं जिनमें राज्य और संघीय स्तर की भागीदारी शामिल है। साहित्य में इन चुनौतियों पर कैसे चर्चा की जा रही है, यह स्पष्ट करने के लिए प्रकाशनों के उद्धरण यहां शामिल किए गए हैं। अतिरिक्त अनुसंधान और नेतृत्व वाले दो बड़े क्षेत्रों पर बाद के खंड में ध्यान दिया गया है।

महिलाओं के आर्थिक अधिकार और पहुंच महिलाओं को सहकारिता के जीवन चक्र के सभी चरणों में धन (वित्तपोषण और पूंजी) की कमी का अनुभव होता है (उदाहरण के लिए, स्टार्ट अप, परिचालन और विस्तार)। एक प्रमुख मुद्दा यह है कि ऋण की शर्तें अक्सर महिलाओं के लिए नुकसानदेह होती हैं। माजुरिन, जो अफ्रीकी संदर्भ की जांच कर रहे थे, ने महिलाओं को ऋण प्राप्त करने में आने वाली बाधाओं को नोट किया, जिसमें "संपार्श्विक की कमी, जटिल प्रशासनिक प्रक्रियाएं, अनुपयुक्त ऋण आकार या ब्याज दरें" शामिल हैं, जो महिला श्रमिकों के "निवेश और उत्पादक क्षमताओं के साथ-साथ उनकी क्षमता को सीमित करती हैं। अन्य बुनियादी और रणनीतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए "(2010)।

सहकारी क्षेत्र के भीतर एक व्यापक मुद्दा जिसने महिलाओं के आर्थिक अवसरों और रोजगार तक पहुंच को प्रभावित करने वाले सामान्य वित्त पोषण के मुद्दों को वित्त पोषण के बाहरी स्रोतों और फंडर्स की अपेक्षाओं के प्रबंधन से संबंधित किया है। विदेशी फंडिंग स्रोतों की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को पूरा करना लैंगिक समानता को कायम रखने और महिला सशक्तिकरण का समर्थन करने से दूर हो सकता है। इसके अतिरिक्त, सहकारी स्वतंत्रता के बजाय, महिला सहकारी समितियां अक्सर दाता और वित्त पोषण एजेंसियों पर निर्भर हो जाती हैं। सहकारी समितियों को खोजने और प्रबंधित करने की महिलाओं की क्षमता सामान्य रूप से आर्थिक भागीदारी के लिए महिलाओं की पहुंच में बाधाओं से संबंधित है, जिसमें व्यवसाय करने की उच्च लागत (जैसे स्टार्ट-अप खर्च, उपकरण प्राप्त करना, और बाजारों में पर्याप्त जगह) और नेविगेट करने की महिलाओं की क्षमता शामिल है। ज्ञान, प्रशिक्षण और शिक्षा तक पहुंच की कमी (जैसे कम प्रबंधकीय और परिचालन अनुभव, निष्पक्ष व्यापार के बारे में ज्ञान की कमी) के कारण व्यापारिक दुनिया। वित्तपोषण और ज्ञान तक पहुंच की कमी के कारण, महिलाओं की बाजारों तक पहुंच की संभावना कम है, अनौपचारिक से औपचारिक अर्थव्यवस्था में स्थानांतरित होने पर उत्पन्न होने वाले मुद्दों को संबोधित करने में सक्षम होने के लिए, और बाजार की मांग और गुणवत्ता के बीच तनाव को दूर करने में सक्षम होने के लिए। माल या सेवाएं। तकनीकी ज्ञान, और विपणन, प्रबंधन और संचालन में कौशल जैसे व्यावसायिक कौशल की महिलाओं की कमी के परिणामस्वरूप कम उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता होती है।

महिलाओं की संगठनात्मक भागीदारी

सहकारिता के भीतर लिंग संबंध मौजूद हैं, जो महिला सदस्यों के खिलाफ भेदभाव करने वाले लिंग शक्ति संबंध और पदानुक्रम बनाते हैं। नेताओं का रवैया और प्रभाव अक्सर महिलाओं पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। जबकि विकासशील देशों में कुछ सहकारी बोर्डों ने महिला कोटा लागू किया है, इन बोर्डों में केवल कुछ ही महिलाएं हैं, एक या दो अधिक से अधिक, और ये कुछ महिलाएं: "निर्णय लेने को प्रभावित नहीं कर सकती हैं और सक्षम नहीं हैं पूरे कार्य प्रणाली को बदलें। अधिकांश देशों में समान प्रतिनिधित्व और नेटवर्किंग की आवश्यकता अभी भी प्राप्त नहीं हुई है" लोधिया (2009)।

नीतियों और उप-नियमों के माध्यम से मुख्य धारा में लिंग की कमी "घरों, समुदायों और स्वयं सहकारी समितियों के भीतर समग्र लिंग पूर्वाग्रहों द्वारा समर्थित है जो शिक्षित पुरुष घरेलू मुखिया और संसाधन-गरीब महिलाओं पर भूमि मालिकों का पक्ष लेते हैं" वोल्डू एट अल (2013)।

महिलाओं की वित्तीय संसाधनों और शिक्षा और प्रशिक्षण तक पहुंच की कमी के कारण, वे सहकारी को ज्ञान और धन का योगदान करने में कम सक्षम हैं। अक्सर महिलाएं परिवार में उनकी भूमिका, सहकारिता में लैंगिक पूर्वाग्रह और शिक्षा और प्रशिक्षण की कमी के कारण सहकारी समितियों के कामकाज और शासन में पूरी तरह से भाग लेने में असमर्थ होती हैं। कब्जे वाले फ़िलिस्तीनी क्षेत्र में, ILO ने महिलाओं की भागीदारी में कई बाधाओं की पहचान की:

साहित्य में पाया गया कि महिलाओं को शासन में नहीं सुना जा रहा था या सहकारी समितियों के भीतर बहस नहीं हो रही थी। सहकारी समितियों में महिलाओं के पास कैरियर में उन्नति के अवसर कम थे और सहकारी समितियों के साथ शिक्षा और प्रशिक्षण तक पहुंच की कमी थी। प्रशिक्षण और शिक्षा की कमी के कारण महिलाएं नेतृत्व में हाशिए पर थीं। एक प्रमुख मुद्दा यह है कि सहकारी उपनियम लिंग के आधार पर अंधे हैं और महिला सदस्यों या कर्मचारियों के लिए अवसर प्रदान नहीं करते हैं। जैसा कि माजुरिन (2010) कहता है, "महिलाओं की सक्रिय और समान भागीदारी हासिल करना - निर्णय लेने को प्रभावित करने और नेताओं के रूप में सहकारी एजेंडा को आकार देने में सक्षम होना, या सदस्यों के रूप में सेवाओं या शिक्षा जैसे लाभों का उपयोग करने में सक्षम होना, उदाहरण के लिए - जो आँकड़ों द्वारा नहीं दिखाया गया है, यह एक और भी बड़ी चुनौती है, हालाँकि सहकारी की लोकतांत्रिक प्रकृति का मतलब यह है कि महिला सदस्य, पुरुषों की तरह, सहकारी मामलों में अन्य प्रकार के उद्यमों की तुलना में अधिक मजबूत आवाज उठा सकती हैं "।

निष्कर्ष

यह पेपर लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को प्राप्त करने के लिए सहकारिता की प्रभावशीलता का एक सिंहावलोकन प्रदान करता है, जैसा कि सहकारी चिकित्सकों, नागरिक समाज संगठनों, शिक्षाविदों और सरकारी कर्मचारियों की एक विस्तृत श्रृंखला द्वारा व्यक्त किया गया है। यह पत्र कई चुनौतियों और रणनीतिक कार्रवाई के

लिए क्षेत्रों पर प्रकाश डालता है, जबकि यह स्वीकार करते हुए कि सुधार के लिए कई प्रासंगिक चर और क्षेत्र हैं। इस पत्र के प्रमुख निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि सहकारी समितियों का महिलाओं पर और आर्थिक गतिविधियों और श्रम शक्ति में उनके समावेश पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह पत्र यह भी बताता है कि सहकारी समितियां नागरिक समाज के साथ सहयोग करके और सरकारी मान्यता प्राप्त करके महिलाओं को सशक्त बनाने की अपनी क्षमता को बढ़ाती हैं। आगे बढ़ते हुए, सहकारी आंदोलन के लिए नेतृत्व में महिलाओं, लैंगिक समानता रणनीतियों और सहकारी समितियों के बीच सहयोग के संबंध में आंतरिक उपायों के माध्यम से लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने की अपनी क्षमता को बेहतर ढंग से प्राप्त करने के कई अवसर हैं। हालांकि, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सहकारी समितियों की क्षमता भी नागरिक समाज के समर्थन और सरकारों द्वारा मान्यता से निर्णायक रूप से लाभान्वित होती है।

References

1. Agarwal, B., 2009. Does Women's Proportional Strength Affect their Participation? Governing Local Forests in South Asia. World Development, 38(1), pp.98–112.

2. Al Madmouj, R., 2012. ILO Initiatives Promoting Women's Participation in Cooperatives in oPt (2009 - 2012), Ramallah / Jerusalem, Israel: ILO.

3. Baden, S., 2013. Women's collective action in African agricultural markets: the limits of current development practice for rural women's empowerment. Gender & Development, 21(2), pp.295–311.

4. Chung, B. (Daisy) et al., 2013. Indicators of Women's Empowerment in Developing Nations. In Workshop in International Public Affairs. Madison, Wisconsin, USA: La Follette School of Public Affairs, p. 95.

5. Daya, S. & Raksha, A., 2012. Self, others and objects in an "alternative economy": Personal narratives from the Heiveld Rooibos Co-operative. Geoforum, 45(5).

6. FAO, 2012a. Agriculture co-operatives and gender equality, Food and Agriculture Organization of the United Nations.

7. FAO, 2012b. Co-operatives: Empowering women farmers, improving food security. Food and Agriculture Organization of the United Nations.

8. Garnevska, E., Liu, G. & Shadbolt, N., 2011. Farmers for Successful Development of Farmer Cooperatives in Northwest China. International Food and Agribusiness Management Review, 14(4).

9. Jones, D.C. & Kalmi, P., 2009. Trust, Inequality, and the Size of the Co-operative Sector: Cross-country evidence. Annals of Public and Co-operative Economics, 80(2), pp.165–195.

10. Jones, E., Smith, S. & Wills, C., 2012. Women producers and the benefit of collective forms of enterprise. Gender & Development, 20(1), pp.13–32.